सचिवालय चलें, सचिवालय चलें। ***दिल्ली के गरीबों की आवाज!***
भोजन के अधिकार की बात करें।। ***हमें पैसे नहीं, हमें चाहिए अनाज!!***

6 से 24 सितम्बर तक रोज़ी रोटी अधिकार अभियान की दिल्ली में यात्रा।

साथियों,
हम सब जानते हैं कि सरकार गरीबी हटाने की जगह गरीबों को हटाने की नीति बनाती आई है। आज के आसमान छूते महंगाई के इस दौर में राशन खरीदना गरीब जनता तो दूर निम्न मध्यम वर्ग के लोगों के बस की बात भी नहीं रही, ऐसे समय में सरकार राशन व्यवस्था को सुधारने और गरीबों को मदद करने के बजाए इन गरीबों का राशन छीनने की योजना बना चुकी है। इसका पायलॉट योजना रधुवीर नगर में चल रहा है, ***जहां महीने भर के राशन के लिए सिर्फ 1000रू दिए जा रहे हैं।*** *सरकार का कहना है कि इससे बच्चों का कुपोषण, भुखमरी, गरीबी सारी समस्याओं का हल हो जाएगा। हम आप से ही पुछना चाहते हैं कि क्या इन पैसों से ये सारी समस्याओं का हल हो जाएगा? हमारा देश जहां विश्व के सर्वाधिक कुपोषित बच्चे रहते हैं और इसकी स्थिति सहारा अफ्रीकी देशों से भी खराब है। 6 वर्ष से कम आयु के आधे से अधिक बच्चे कुपोषित हैं जिन्हे सुधारने के लिए अंगनवाड़ी (ICDS) के तहत दी जाने वाली भोजन के गुणवत्ता को बढ़ाना होगा एंव इसके लिए सरकार को एक सशक्त राशन प्रणाली लाने की आवश्यकता है, लेकिन सरकार राशन व्यवस्था को ही बंद करना चाहती है। रोज़ी रोटी अधिकार अभियान दिल्ली सरकार के इस नीति का पुरज़ोर विरोध करती है।*

रोज़ी रोटी अधिकार अभियान *दिल्ली ने गरीबों की प्राथमिकताएँ समझने के लिए 4005 परिवारों का सर्वेक्षण किया इसमें दिल्ली के विभिन्न झुग्गी बस्तियों, पूनर्वास कॉलोनियों एंव बेघर व्यक्तियो को शामिल किया गया था।* ***इस सर्वे में सभी उत्तरदाताओं में से 91.4%का कहना था कि उन्हे नकद हस्तांतरण के स्थान पर एक मजबूत राशन व्यवस्था चाहिए, जबकि सिर्फ 5%का कहना था कि उन्हे राशन के स्थान पर नकद हस्तांतरण चाहिए जबकि शेष उत्तरदाताओं की कोई राय नहीं थी।*** *सर्वे में यह भी पाया गया कि इन इलाकों में रहने वाले दिहाड़ी मजदूरों में से सिर्फ 31.5% के पास ही बीपीएल कार्ड था, जबकि कईयों को राशन नहीं मिलने का कारण था कि उनके पास राशन कार्ड नहीं थे या जो राशन कार्ड थे उन पर मुहर नहीं लगी हुई थी अथवा रद्द कर दिए गए थे या उनका नवीनीकरण या बायोमेट्रिक नहीं हुआ था। राशन दूकान बंद रहती है या दूकानदार राशन देने से मना कर देता है इस प्रकार की समस्यायें भी सामने आई।*

अध्ययन में पाया गया कि दिल्ली में प्रभावी राशन प्रणली के लिए राशन व्यवस्था में व्यापक सुधार की आवश्यकता है, किन्तु लोगों का कहना था कि उन्हे राशन व्यवस्था में सुधार चाहिए न कि नकद हस्तांतरण। दिल्ली की विभिन्न बस्तियों में हमारे हाल के अभियान एवं सर्वे के परिप्रेक्ष्य में हमारी निम्न मांगें हैं :

1. दिल्ली में राशन व्यवस्था (पीडीएस) को समाप्त करने के बजाए इसे और मजबूत करो एवं इसके अंतर्गत चावल एवं गेहूँ के साथ ही साथ दालें, चीनी, मिट्टी का तेल, खाद्य तेल एवं मोटे अनाज को भी शामिल करो।

2. यह स्पष्ट हो चुका है कि लक्षित प्रणाली असफल हो चुकी है अतः राशन व्यवस्था (पीडीएस) का सर्वव्यापीकरण करो और लोगों को विभाजित करनेवाली एपीएल/बीपीएल नीति बंद कारो।

3. राशन व्यवस्था (पीडीएस) में सुधार के लिए तत्काल कदम उठाए जाएँ जिसके तहत पारदर्शिता बढ़ाना, सशक्त शिकायत निवारण प्रणाली, राशन दूकान द्वारा घर घर जा कर राशन वितरण, पूर्ण कम्पूटिरीकरण एवं राशन दूकानदारों के विरूद्ध तत्काल कार्यवाही आदि।

4. राशन कार्डों के नवीनीकरण की समस्या से जुझ रहे दिल्ली वासियों की समस्या का तत्काल समाधान किया जाए।

हम ये मांग करते है कि बड़ी नीतियाँ (जैसे राशन व्यवस्था "पीडीएस" को समाप्त कर प्रत्यक्ष नकद हस्तांतरण लाना) बनाने से पहले इस पर व्यापक बहस हो विशेष कर उनलोगों के साथ जो सीधे तौर पर इससे प्रभावित हैं। सरकार को दिल्ली की राशन व्यवस्था मजबूत करने के लिए दिल्ली के विभिन्न बस्तियों में गरीब लोगों के साथ अवश्य विचार विमर्श करना चाहिए। इस संदर्भ में हम आप सभी से अपील करते हैं कि अधिक से अधिक संख्या में आकर अभियान की यात्रा में शामिल हों और विशाल रैली को सफल बनाऐं। **ये यात्रा 6 से 24 सितम्बर तक दिल्ली के विभिन्न बस्तियों से होकर जाएगी। यात्रा का आरम्भ 6 सितम्बर 2011 को 11बजे शहीद पार्क, बहादूर शाह ज़फर मार्ग से होगी।** 26 सितम्बर को एक विशाल रैली निकाली जाएगी जो दिल्ली सचिवालय पर जा कर समाप्त होगी।

एपील–बीपीएल बंद करो! सबको सस्ता राशन दो!
पैसा नहीं अनाज चाहिए!!

संपर्क : धर्मेंद्र यादव : 9968005632.
रोज़ी रोटी अधिकार अभियान दिल्ली, एन. एफ. आई. डब्ल्यू. 1002, दसवीं मंजिल, अंसल भवन, कस्तूरबा गाँधी मार्ग, नई दिल्ली – 11001, फोन नम्बर : 011 23319541,